Hindustan (Date: - 07/02/2020)

जल-जीवन-हरियाली होगी थीम

बिहार दिवस

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के स्थापना दिवस (22 मार्च) पर हर साल मनाया जाने वाला बिहार दिवस समारोह की इस बार मुख्य थीम 'जल-जीवन-हरियाली' होगी। इसी विषय पर केंद्रित कर आयोजन की तमाम गतिविधियां सरकार के सभी विभाग और सभी जिले संचालित करेंगे। बिहार दिवस समारोह 22 से 24 मार्च तक तीन दिनों तक मनाया जाएगा।

गुरुवार को बिहार दिवस के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग के

तैयारी

- शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने की समारोह को लेकर बैठक
- शिक्षा परियोजना परिषद को बनाया गया आयोजन का नोडल

अपर मुख्य सचिव आरके महाजन की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। उनके कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपी) को तीन दिवसीय समारोह का मुख्य नोडल बनाया गया। बैठक में माध्यमिक निदेशक गिरिवर दयाल सिंह, बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह, विशेष सचिव सतीश चन्द्र झा, जनशिक्षा निदेशक कुमार रामानुज, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक विनोदानंद झा, बीईपी की विभा कुमारी समेत तमाम निदेशालयों के अफसर मौजूद रहे। बैठक के बाद बीईपी निदेशक संजय सिंह ने निर्णयों की जानकारी दी। आयोजन के लिए अगले दो-तीन दिनों में तमाम कमेटियों का गठन करने का निर्देश आरके महाजन ने अधिकारियों को दिया।

बिहार दिवस समारोह वैसे तो राज्यभर में मनाया जाएगा, लेकिन मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। गांधी मैदान के मुख्य मंच पर देश के नामचीन गायकों की प्रस्तुतियां होंगी।

Prabhat Khabar (Date: - 07/02/2020)

पटना सिटी और दानापुर में खुलेगा वायु जांच केंद्र

बजट पूर्व समीक्षा बैठक करते डिप्टी सीएम, डॉ एस सिद्धार्थ व अन्य.

संवाददाता ▷ पटना

डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2020-21 के दौरान राज्य भर में वायु की गुणवत्ता परखने के लिए 24 नये केंद्र स्थापित किये जायेंगे. इनकी मदद से राज्य भर में प्रदूषण की स्थिति का सटीक आकलन हो सकेगा. वर्तमान में ऐसे तीन केंद्र पटना में काम कर रहे हैं. पटना सिटी और दानापुर में दो नये केंद्र खुलेंगे. वहीं मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया में एक-एक केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जो जल्द काम करने लगेंगे. डिप्टी सीएम गुरुवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बजट पूर्व समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पटना के अलावा दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ क्षेत्र में 15 साल या इससे पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. मार्च, 2021 के बाद पूरे राज्य में डीजल से चलने वाले ऑटो प्रतिबंधित हो जायेंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सवारी वाहनों खासकर ऑटो को सीएनजी में तब्दील करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर अनुदान योजना चला रही है. पटना में पांच ऑउटलेटों में तीन से सीएनजी आपूर्ति शुरू हो गयी है. डिप्टी सीएम ने कहा कि यूएनडीपी तथा हिंदुस्तान कोका-कोला बिवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की गर्दनीबाग में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग इकाई लग रही है. मेडिकल अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए भोजपुर व मधेपुरा में केंद्र बनेंगे. बैठक में यूएनडीपी, गेल, आइओसी, भारत पेट्रोलियम, बुडको, ब्रेडा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज समेत अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. एके घोष, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

वायु प्रदूषण पर शोध

पटना. राज्य में वायु प्रदूषण कम करने के लिए शोध होगा. इसके लिए शोधार्थियों की बहाली जल्द की जायेगी और ये सभी शोधार्थी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत जलवायु परिवर्तन संभाग में काम करेंगे. प्राथमिकता के आधार पर पहले चरण में पटना, गया, मुजफ्फरपुर जिलों के वायु प्रदूषण को लेकर शोध किया जायेगा.

Prabhat Khabar (Date: - 07/02/2020)

बिहार मॉडल अपनायेगा कर्नाटक

- कर्नाटक टीम ने बिहार आकर जाना लोक शिकायत निवारण प्रणाली को

संवाददाता ▷ पटना

आरटीपीजीएस प्रणाली का निरीक्षण करती कर्नाटक की टीम.

राज्य की लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (आरटीपीजीएस) के तहत काम करने वाली प्रणाली के बारे में जानकारी लेने के लिए कर्नाटक सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार का दौरा किया. इस दौरान कर्नाटक के अधिकारियों ने इसे जन उपयोगी बताते हुए इसकी सराहना भी की. पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन होने की प्रशंसा करते हुए इस मॉडल को कर्नाटक में लागू करने को लेकर सकारात्मकता दिखायी है. गौरतलब है कि इससे पहले भी कर्नाटक के पदाधिकारियों की एक टीम बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) का अध्ययन करने बिहार आ चुकी है. इसे बाद में कर्नाटक ने अपने यहां लागू भी किया था. कर्नाटक के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (इ-गवर्नेंस) के वरीय अधिकारी और स्मार्ट गवर्नेंस सेंटर के कार्यपालक निदेशक सुनील पंवार की अगुआई में आयी टीम ने पांच और छह फरवरी को बिहार का दौरा किया. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की अपर मिशन निदेशक डॉ प्रतिमा ने इस दल के समक्ष इस अधिनियम से जुड़ी एक विस्तृत प्रस्तुति दी. इसके बाद कर्नाटक की टीम ने राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र और लोक शिकायत निवारण कार्यालय का दौरा किया.